भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 178
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता

178* श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य में दक्षिणी ग्रिड के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता और भार प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता की वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन में नई निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने और समायोजित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

“तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता” के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) और (ख) : तमिलनाडु राज्य में संस्थापित उत्पादन क्षमता 43,107 मेगावाट है। अगले तीन वर्षों में राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) अगले तीन वर्षों में राज्य क्षेत्र में 3,440 मेगावाट तापविद्युत क्षमता और 500 मेगावाट पंप भंडारण क्षमता शुरू की जानी है।
- (ii) अगले तीन वर्षों में शुरू होने वाली न्यूक्लियर परियोजनाओं से तमिलनाडु को लगभग 2,151.8 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा।
- (iii) राज्य में अगले तीन वर्षों में लगभग 6,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता शुरू की जानी है।
- (iv) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) परियोजना जैसी स्कीमों की शुरुआत की गई है।

तमिलनाडु उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरिडोर के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से सुदृढ़ता से जुड़ा हुआ है, जिसमें 765 केवी और 400 केवी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) एसी लाइनों के साथ-साथ +/-800 केवी उच्च वोल्टेज (एचवी) डीसी सिस्टम शामिल हैं, जो तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/राष्ट्रीय ग्रिड के बीच अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के सुचारु अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

विभिन्न अंतर-क्षेत्रीय लिंक जैसे- नरेंद्र (दक्षिणी क्षेत्र) से पुणे (पश्चिमी क्षेत्र) 765 केवी डी/सी लाइन, अंगुल (पूर्वी क्षेत्र) से श्रीकाकुलम (दक्षिणी क्षेत्र) 765 केवी द्वितीय डी/सी लाइन और बीदर (दक्षिणी क्षेत्र) से परली (पश्चिमी क्षेत्र) 765 केवी डी/सी लाइन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये अंतर-क्षेत्रीय लिंक, दक्षिणी क्षेत्र के उच्चतम मांग अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करेंगे। ये लिंक दक्षिणी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत के निर्यात को भी सुगम बनाएंगे।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है।

भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में विद्युत उत्पादन, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) अगले दस वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा आबद्ध की जाने वाली क्षमता को दर्शाने वाली संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार की गई है। इससे निजी क्षेत्र सहित विद्युत उत्पादनकर्ताओं को तमिलनाडु सहित देश में उत्पादन क्षमता स्थापित करने की संभावना प्राप्त हुई है।
- (ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोली जारी करने के लिए बोली प्रक्षेप पथ जारी किया है।
- (iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं, दिसंबर, 2030 तक हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और दिसंबर, 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- (iv) देश में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता वृद्धि के एकीकरण की सुगमता के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पारेषण योजना अर्थात् "वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणाली" तैयार की गई है। इसमें तमिलनाडु में 8 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा सहित) की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली शामिल है, जिसमें से 1.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) पहले ही शुरू हो चुकी है; 1 गीगावाट (0.5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा सहित) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए, पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) कार्यान्वयनाधीन है और 5.0 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की पहचान की गई है और इसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।
- (v) स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (vi) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और उसे सुगम बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों का संकेत दिया गया है।

- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए उप-स्टेशन क्षमता निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराई गयी है।
- (x) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई है।
- (xi) सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 7,453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 1 गीगावाट क्षमता की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी, जिसमें से 500 मेगावाट क्षमता तमिलनाडु के तट पर स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) तमिलनाडु सरकार द्वारा निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पम्प स्टोरेज परियोजनाओं और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 10 मेगावाट तक) की स्थापना के लिए नीतियाँ जारी की गई हैं।
- (ii) तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों में कुल 13,500 मेगावाट क्षमता वाली पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है और इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत स्थापित किया जाना है।
- (iii) स्व-चिह्नित पम्प स्टोरेज परियोजनाओं और लघु जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, अभिरुचि पत्र आमंत्रित करके विकासकर्ताओं की पहचान की गई है और आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1857
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

लद्दाख के गाँवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति

1857. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सभी गाँवों में सर्दियों के महीनों के दौरान 24x7 बिजली उपलब्ध हो जाती है जब सौर ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लद्दाख के दूर-दराज के गाँवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर ली जाएगी और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए 220 किलो वोल्ट श्रीनगर-लेह विद्युत लाइन परियोजना के संबंध में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या लद्दाख में अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी ऊर्जा कंपनियों के साथ किसी साझेदारी की संभावना तलाशी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में सरकारी भवनों और रक्षा प्रतिष्ठानों की कार्बन-तटस्थ ऊर्जा संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं।

भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान की है और वर्तमान में सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सहायता प्रदान कर रही है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नुब्रा, ज़ास्कर और चांगथांग क्षेत्रों में वर्तमान में लघु जलविद्युत परियोजनाओं, सौर पीवी संयंत्रों और डीजल जनरेटरों द्वारा ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, 220 केवी नुब्रा और ज़ास्कर पारेषण लाइन और हिम्या से न्योमा और खारु से दुरबुक तक 66 केवी लाइन निर्माणाधीन है। आरडीएसएस के तहत, 687 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें चांगथांग क्षेत्र को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 567 करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

(ग): संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 220 केवी श्रीनगर-लेह पारेषण लाइन की 335 किलोमीटर लंबाई पहले ही पूरी हो चुकी है और यह वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। इससे आगे सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए, निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं:

- i. 220 केवी फ्यांग-डिस्केट (नुब्रा) पारेषण लाइन: कुल 265 टावरों में से 90 टावर स्थापित किए जा चुके हैं और 224 टावर की नींव तैयार है। 17.67 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का कार्य पूरा हो चुका है।
- ii. 220 केवी द्रास-पदुम (ज़ास्कर) पारेषण लाइन: कुल 675 टावरों में से 339 टावर स्थापित किए जा चुके हैं और 577 टावर की नींव तैयार है। 27.77 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अक्टूबर, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।

(घ) : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने अपने क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा/भंडारण परियोजनाओं के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं की सूचना दी है:

- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ तारु में 40 मेगावाट घंटा सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के साथ 25 मेगावाट एसी, 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास इसका कार्य आवंटित हो चुका है और प्रगति पर है।
- स्टाकना जलविद्युत परियोजना स्थल पर 9 मेगावाट बीईएसएस के साथ 7 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की पहचान की गई है और रेस्को मॉडल पर बोली प्रक्रियाधीन है।
- नुब्रा में 12 मेगावाट बीईएसएस के साथ 1.5 मेगावाट (एसी), 4.5 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा परियोजना, और ज़ास्कर में रेस्को मॉडल पर 12 मेगावाट बीईएसएस सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 6 मेगावाट एसी।

(ङ) : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी भवनों और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए कार्बन-तटस्थ ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1867
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत योजना

1867. श्री दुलू महतो:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्युत योजना के अंतर्गत वर्ष 2032 तक अधिकतम अनुमानित विद्युत मांग कितनी होगी;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2032 तक उपरोक्त मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य पारेषण प्रणालियों में अनुमानित वृद्धि कितनी है;

(ग) वर्ष 2032 तक अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता में अनुमानित वृद्धि कितनी है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया विनिर्माण के संभावित केंद्रों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय विद्युत योजना 2032 के संबंध में सरकार की पहल से मध्य प्रदेश, विशेष रूप से देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास में किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) के अनुसार, वर्ष 2022-32 की अवधि के लिए, अखिल भारतीय उच्चतम विद्युत मांग वर्ष 2031-32 तक 388 गीगावाट होने का अनुमान है। भारत सरकार को विश्वास है कि इस अनुमानित विद्युत मांग को बिना किसी कमी के पूरा किया जा सकेगा।

(ख) : अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के अंतर्गत वर्ष 2031-32 तक नियोजित की गई पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक) का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को जून, 2025 के लगभग 120 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2031-32 तक 168 गीगावाट करने की योजना है।

(घ) : प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया उत्पादन के कारण वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त विद्युत मांग लगभग 70 गीगावाट है। गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों तक विद्युत आपूर्ति के लिए पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है। नियोजित पारेषण प्रणाली को हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की स्थापना की प्रगति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों तक विद्युत आपूर्ति के लिए नियोजित पारेषण प्रणाली का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ङ) : महाराष्ट्र राज्य सहित पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2025 तक) के लिए ऊर्जा की दृष्टि से देश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(च) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड-II पारेषण) के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-32 के दौरान अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में लगभग 2030 सीकेएम पारेषण लाइनें और 27.5 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर) जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-32 के दौरान अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) में लगभग 4,292 सीकेएम पारेषण लाइनें और उप-स्टेशनों में 16.54 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर) जोड़ने की योजना है।

देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र के आसपास, वर्ष 2032 तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) और आईएनएसटीएस के तहत निम्नलिखित नए सबस्टेशन/मौजूदा सबस्टेशनों पर

आईसीटी संवर्धन की योजना बनाई गई है, जिससे निर्वाचन क्षेत्र की विद्युत मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

- (i) नया 220/132 केवी, 160 एमवीए सुपर कॉरिडोर (इंदौर) सबस्टेशन (आईएनएसटीएस)
- (ii) 220/132 केवी, 160 एमवीए मांगलिया सबस्टेशन पर आईसीटी संवर्धन (आईएनएसटीएस)
- (iii) 765/400 केवी इंदौर सबस्टेशन पर आईसीटी संवर्धन (आईएनएसटीएस)
- (iv) 400/200 केवी पचौरा एसईजेड पर आईसीटी संवर्धन (आईएसटीएस)
- (v) 400/220 केवी शुजालपुर (पीजी) सबस्टेशन पर आईसीटी संवर्धन (आईएसटीएस)
- (vi) 400/220 केवी राजगढ़ सबस्टेशन पर आईसीटी संवर्धन (आईएसटीएस)

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के अंतर्गत वर्ष 2031-32 तक नियोजित पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक) का विवरण

		30.06.2025 की स्थिति के अनुसार	जुलाई, 2025 से मार्च,2032 के दौरान नियोजित वृद्धि	वर्ष 2031-32 के अंत में (31.03.2032)	कुल
पारेषण लाइन (सीकेएम)	आईएसटीएस	2,14,677	79,868	2,94,545	6,48,190
	अंतरराज्यीय :	2,80,728	72,917	3,53,645	
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए)	आईएसटीएस	5,68,205	7,13,150	12,81,355	24,11,885
	अंतरराज्यीय :	7,91,498	3,39,032	11,30,530	

हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु नियोजित पारेषण प्रणाली का विवरण:

- (i) गुजरात के नवीनल (मुंद्रा) क्षेत्र में विद्युत की निकासी हेतु नेटवर्क विस्तार स्कीम (चरण-1: भाग-क के अंतर्गत)
- (ii) चरण-1: भाग-ख स्कीम के अंतर्गत गुजरात के मुंद्रा क्षेत्र में संभावित हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली
- (iii) मुंद्रा, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली, चरण-11
- (iv) चरण-3 के अंतर्गत मुंद्रा, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली
- (v) चरण-4 के अंतर्गत मुंद्रा, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली
- (vi) गुजरात के कांडला क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली (चरण-1)
- (vii) गुजरात के कांडला क्षेत्र में संभावित ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया केन्द्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली (चरण-11)
- (viii) गुजरात के कांडला क्षेत्र में संभावित ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया केन्द्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली (चरण-11)
- (ix) काकीनाडा में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली
- (x) पारेषण पुदिमडका (विशाखापट्टनम) में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली
- (xi) रामायापट्टनम में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xii) तूतीकोरिन में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र की विद्युत मांग को पूरा करने हेतु पारेषण प्रणाली

(xiii) मैंगलोर में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xiv) पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXIV (ईआरईएस-XXXIV): पारादीप में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु

(xv) पूर्वी क्षेत्र विस्तार स्कीम-XXXIX (ईआरईएस-XXXIX): गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु

(xvi) गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xvii) पारादीप और केंद्रपाड़ा में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xviii) मलकानगिरी में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xix) रायगढ़ में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

(xx) श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया निर्माण केंद्र में विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण प्रणाली

वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2020-2021 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में महाराष्ट्र सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र /क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,732	1,732	0	0	1,523	1,523	0	0
दिल्ली	33,086	33,077	9	0	29,560	29,555	4	0
हरियाणा	54,505	54,492	13	0	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	10,424	10,353	71	0.7	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	20,025	16,259	3,767	18.8	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	56,776	56,770	6	0	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	81,281	81,222	58	0.1	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	1,22,549	1,21,004	1,545	1.3	1,24,367	1,23,383	984	0.8
उत्तराखंड	14,472	14,376	96	0.7	13,827	13,818	8	0.1
उत्तरी क्षेत्र	3,94,851	3,89,285	5,566	1.4	3,96,151	3,92,323	3,829	1
छत्तीसगढ़	30,111	30,107	4	0	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	1,13,940	1,13,939	1	0	1,11,622	1,11,622	0	0
मध्य प्रदेश	76,172	76,172	0	0	83,437	83,437	0	0
महाराष्ट्र	1,55,167	1,55,166	0	0	1,50,679	1,50,663	16	0
दमन और दीव	2,574	2,574	0	0	2,223	2,223	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	6,528	6,528	0	0	5,497	5,497	0	0
गोवा	4,350	4,350	0	0	4,083	4,083	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	3,88,841	3,88,836	5	0	3,88,013	3,87,975	38	0
आंध्र प्रदेश	65,452	65,414	38	0.1	62,080	62,076	4	0
तेलंगाना	68,306	68,303	3	0	66,998	66,994	4	0
कर्नाटक	72,799	72,796	3	0	68,851	68,831	19	0
केरल	26,315	26,265	50	0.2	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	1,08,816	1,08,812	4	0	1,01,194	1,01,189	5	0
पुदुचेरी	2,847	2,846	1	0	2,644	2,644	0	0
लक्षद्वीप (#)	46	46	0	0	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,44,535	3,44,436	99	0	3,26,885	3,26,836	48	0
बिहार	31,627	31,533	94	0.3	34,171	34,018	153	0.4
डीवीसी	22,429	22,427	2	0	21,368	21,368	0	0
झारखंड	8,941	8,872	69	0.8	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	29,692	29,692	0	0	29,848	29,848	0	0
पश्चिम बंगाल	52,948	52,824	124	0.2	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	554	554	0	0	546	546	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	1,46,191	1,45,902	289	0.2	1,47,530	1,46,999	531	0.4

अरुणाचल प्रदेश	753	749	4	0.5	719	714	5	0.7
असम	9,804	9,288	516	5.3	10,192	9,815	377	3.7
मणिपुर	924	917	6	0.7	974	969	5	0.5
मेघालय	2,112	2,064	48	2.3	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	647	643	4	0.7	728	723	4	0.6
नागालैंड	814	809	5	0.7	826	822	4	0.5
त्रिपुरा (*)	1,538	1,515	23	1.5	1,484	1,481	3	0.2
पूर्वोत्तर	16,591	15,984	607	3.7	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारतीय	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी /विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में महाराष्ट्र सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6
उत्तरी क्षेत्र	4,17,934	4,13,915	4,019	1
छत्तीसगढ़	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,72,823	1,72,809	14	0
दमन और दीव	2,594	2,594	0	0
दादरा और नगर हवेली	6,839	6,839	0	0
गोवा	4,448	4,448	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,29,065	4,28,683	383	0.1
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0
केरल	26,579	26,570	9	0
तमिलनाडु	1,09,816	1,09,798	18	0
पुडुचेरी	2,894	2,893	1	0
लक्षद्वीप (#)	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,50,678	3,50,421	258	0.1
बिहार	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	23,741	23,736	4	0
झारखंड	11,148	10,590	558	5
ओडिशा	38,339	38,332	7	0
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	610	609	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	335	327	8	2.3
पूर्वी क्षेत्र	1,64,054	1,62,973	1,081	0.7
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1
असम	10,844	10,825	19	0.2

मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	656	644	12	1.8
नागालैंड	852	851	1	0.1
त्रिपुरा (*)	1,578	1,578	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,079	18,033	47	0.3
अखिल भारतीय	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में महाराष्ट्र सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप (#)	64	64	0	0	64	64	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.18562
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा (*)	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
अखिल भारतीय	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में महाराष्ट्र सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	555	555	0	0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	11,303	11,299	4	0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	18,816	18,757	59	0.3
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	3,387	3,375	11	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	4,853	4,847	6	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	20,885	20,860	25	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	28,036	28,036	0	0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	46,028	46,022	6	0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	4,426	4,417	10	0.2
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	1,38,697	1,38,576	121	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	11,474	11,472	2	0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	41,752	41,752	0	0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	25,168	25,166	2	0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0	52,395	52,393	1	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,852	10,852	0	0	2,845	2,845	0	0
गोवा	5,411	5,411	0	0	1,486	1,486	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0	1,38,472	1,38,466	6	0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	20,471	20,471	0	0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	19,690	19,690	0	0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	22,945	22,945	0	0
केरल	31,624	31,616	8	0	8,015	8,015	0	0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	34,817	34,817	0	0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0	948	946	2	0.2
लक्षद्वीप (#)	68	68	0	0	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0	1,06,899	1,06,897	2	0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	12,716	12,713	4	0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	6,368	6,367	1	0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	3,931	3,930	1	0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	11,830	11,828	2	0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	20,645	20,626	18	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	128	128	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	425	413	12	2.9	107	104	3	2.8
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	55,637	55,611	26	0

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	283	283	0	0
असम	12,843	12,837	6	0	3,506	3,506	0	0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	274	272	2	0.9
मेघालय	2,046	2,046	0	0	494	494	0	0
मिजोरम	709	709	0	0	177	177	0	0
नागालैंड	938	938	0	0	243	243	0	0
त्रिपुरा (*)	1,939	1,939	0	0	512	512	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	5,492	5,490	2	0
अखिल भारतीय	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	4,45,197	4,45,040	157	0

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1877
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

दैनिक बिजली की आवश्यकता और उत्पादन

1877. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिदिन कितनी यूनिट बिजली की आवश्यकता है और उसका कितने यूनिट का उत्पादन होता है;

(ख) क्या देश वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयले से ऊर्जा उत्पादन बंद करके केवल आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के पूर्ण रूप से कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2025 तक) के लिए विद्युत की औसत आवश्यकता एवं प्रतिदिन उत्पादन (एमयू/दिन) का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.819 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 260.784 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में परिवर्तित हो गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

ये विवरण दर्शाते हैं कि देश में विद्युत की बेहतर उपलब्धता के साथ, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान घटकर केवल 0.1% के मामूली स्तर पर आ गया है और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान और भी कम होकर लगभग शून्य हो जाएगा।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से क्षमता वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी है। मई, 2023 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, कोयला आधारित संस्थापित क्षमता का हिस्सा, जो जून, 2025 में लगभग 46% है, वर्ष 2031-32 में घटकर लगभग 30% होने की संभावना है। हालाँकि, कोयले से ऊर्जा उत्पादन बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापविद्युत (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापविद्युत क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है। अप्रैल, 2023 से जून, 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापविद्युत क्षमताएँ पहले ही चालू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट की संकटग्रस्त तापविद्युत परियोजनाओं सहित) तापविद्युत क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापविद्युत क्षमता के लिए संविदा प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के जून, 2025 तक विद्युत की औसत आवश्यकता एवं प्रतिदिन उत्पादन (एमयू/दिन) का विवरण।

वित्त वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	कुल उत्पादन
	(एमयू/दिन)	(एमयू/दिन)
2022-23	4147	4450.59
2023-24	4443	4751.62
2024-25	4641	5012.87
2025-26 (जून, 2025 तक)	4892	5230.25

टिप्पणी: प्रतिदिन एमयू की गणना वर्ष के दौरान कुल ऊर्जा आवश्यकता/उत्पादन को उस वर्ष के दिनों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

लो.स.अता.प्र.स.-1877

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून 2025 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति की गई	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2022-23	1513497	1505914	7583	0.5
2023-24	1626132	1622020	4112	0.3
2024-25	1693959	1692369	1590	0.1
2025-26 (जून, 2025 तक)	445197	445040	157	0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1896
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस के तहत स्वीकृत स्मार्ट मीटर

1896. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरों की कुल संख्या राज्यवार और वर्षवार तथा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिलावार कितनी है;

(ख) आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस के अंतर्गत कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है और यदि हाँ, तो जिलावार और सामाजिक श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने स्मार्ट मीटर संस्थापना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत अब तक संस्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक संस्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरों का जिलावार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

(ग) : उत्तर प्रदेश में आर.डी.एस.एस. के अंतर्गत अब तक संस्वीकृत और विद्युतीकृत घरों का जिलावार विवरण अनुबंध-IV पर दिया गया है।

(घ) : स्मार्ट मीटर स्थापना अभी अपने प्रारंभिक कार्यान्वयन चरण में है। स्मार्ट मीटर स्थापना के प्रभाव का आकलन तब किया जा सकता है जब पर्याप्त संख्या में स्मार्ट मीटर स्थापित हो जाएँ। बिहार और असम जैसे राज्यों में, जहाँ पर्याप्त संख्या में स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके हैं, स्मार्ट मीटर स्थापना का प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है:

i. समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ:

राज्य	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 24
असम	18.73%	14.03%
बिहार	35.33%	20.32%

ii. आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर रु./किलोवाट घंटे में :

राज्य	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 24
असम	0.1	(0.22)
बिहार	0.72	(0.18)

iii. वार्षिक पीएटी/(हानि) करोड़ रुपये में:

राज्य	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 24
असम	(292)	384
बिहार	(1,942)	1,411

जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं से देखा जा सकता है, दोनों राज्यों ने प्रचालनात्मक और वित्तीय दोनों मानकों के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद, अन्य राज्यों में भी ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा।

आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर का विवरण

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्वीकृत (संख्या)	संस्थापित (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार	84,835	0
2	आंध्र प्रदेश	59,19,344	16,82,446
3	अरुणाचल प्रदेश	2,98,250	17,086
4	असम	64,45,127	37,47,655
5	बिहार	26,07,153	20,47,465
6	छत्तीसगढ़	61,79,479	22,82,766
7	दिल्ली	3,521	0
8	गोवा	7,50,356	0
9	गुजरात	1,67,87,587	20,94,432
10	हिमाचल प्रदेश	28,41,908	4,59,945
11	जम्मू और कश्मीर	14,97,690	2,00,224
12	झारखंड	13,62,044	2,90,516
13	केरल	1,33,83,001	0
14	मध्य प्रदेश	1,34,29,206	22,43,063
15	महाराष्ट्र	2,40,04,866	49,30,410
16	मणिपुर	1,66,208	8,867
17	मेघालय	4,72,743	0
18	मिजोरम	2,92,081	1,768
19	नागालैंड	3,23,878	7,361
20	पुदुचेरी	4,07,052	0
21	पंजाब	89,81,414	0
22	राजस्थान	1,47,36,692	3,59,848
23	सिक्किम	1,48,542	42,985
24	तमिलनाडु	3,04,90,774	0
25	त्रिपुरा	5,62,870	92,108
26	उत्तर प्रदेश	2,85,26,731	32,78,563
27	उत्तराखंड	16,49,684	2,10,679
28	पश्चिम बंगाल	2,10,35,262	5,13,457
	अखिल भारतीय कुल	20,33,88,298	2,45,11,644

आरडीएसएस के तहत उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों का जिलावार विवरण

क्रम सं.	डिस्कॉम	ज़िला	संस्वीकृत (संख्या)	संस्थापित (संख्या)
1	पीयूवीवीएनएल	आजमगढ़	6,05,284	36,656
		बलिया	3,14,303	59,449
		बस्ती	3,52,686	32,353
		चंदौली	2,48,363	55,761
		देवरिया	3,75,784	32,555
		फतेहपुर	3,63,972	62,527
		गाजीपुर	4,28,537	74,194
		गोरखपुर	7,04,224	1,41,385
		जौनपुर	5,98,440	47,925
		कौशांबी	2,05,140	40,409
		कुशीनगर	3,97,196	33,023
		महाराजगंज	3,56,007	43,655
		मऊ	3,29,096	47,540
		मिर्जापुर	3,20,250	56,626
		प्रतापगढ़	4,62,404	82,476
		प्रयागराज	4,74,649	47,048
		संतकबीरनगर	2,32,630	24,015
		संत रविदास नगर	1,91,035	50,112
		सिद्धार्थनगर	3,14,808	23,668
	सोनभद्र	2,69,044	38,349	
वाराणसी	2,06,684	61,259		
	पीयूवीवीएनएल कुल		77,50,536	10,90,985
2	एमवीवीएनएल	अम्बेडकरनगर	3,41,290	15,942
		अमेठी	3,41,291	12,650
		अयोध्या	3,41,296	36,907
		बदायूं	3,80,772	27,462
		बहराइच	4,38,521	27,507
		बलरामपुर	2,14,742	19,628
		बाराबंकी	3,41,293	18,323
		बरेली	6,04,657	62,448
		गोंडा	4,61,487	37,318
		हरदोई	3,32,350	30,832
		लखीमपुर खीरी	5,74,612	57,784
		लखनऊ	10,93,296	1,09,294
		पीलीभीत	3,19,480	78,218
		रायबरेली	5,59,826	53,194
		शाहजहांपुर	3,69,663	38,135
		श्रावस्ती	1,98,944	4,723
		सीतापुर	2,88,288	39,554
सुल्तानपुर	3,41,290	21,811		

क्रम सं.	डिस्कॉम	ज़िला	संस्वीकृत (संख्या)	संस्थापित (संख्या)
		उन्नाव		
			3,70,542	43,167
	एमवीवीएनएल कुल		79,13,640	7,34,897
3	डीवीवीएनएल	आगरा	4,46,572	81,835
		अलीगढ़	4,28,888	1,19,116
		औरैया	2,16,861	9,302
		बाँदा	3,04,858	19,105
		चित्रकूट	1,72,598	3,904
		एटा	2,38,445	21,721
		इटावा	1,82,576	6,244
		फर्रुखाबाद	2,18,538	26,033
		फिरोजाबाद	3,16,422	56,306
		हमीरपुर	2,04,373	15,825
		हाथरस	2,68,056	60,095
		जालौन	2,70,335	26,743
		झांसी	3,34,800	77,035
		कन्नौज	2,37,939	34,812
		कानपुर देहात	2,71,912	8,234
		कानपुर नगर	2,62,502	15,864
		कासगंज	2,12,302	27,660
		ललितपुर	1,62,424	17,827
		महोबा	1,54,548	15,450
		मैनपुरी	2,84,021	58,434
	मथुरा	3,57,402	42,438	
	डीवीवीएनएल कुल		55,46,372	7,43,983
4	पीवीवीएनएल	अमरोहा	3,17,708	25,048
		बागपत	2,54,249	4,351
		बिजनौर	6,64,248	49,174
		बुलन्दशहर	5,97,338	50,646
		गौतम बुद्ध नगर	3,56,425	16,737
		गाजियाबाद	9,89,348	59,931
		हापुड	2,76,747	14,063
		मेरठ	6,14,850	1,17,131
		मुरादाबाद	5,68,818	84,108
		मुजफ्फरनगर	5,30,974	53,584
		रामपुर	3,76,461	36,674
		सहारनपुर	5,95,716	58,475
		संभल	2,89,211	24,677
	शामली	2,51,681	80,821	
	पीवीवीएनएल कुल		66,83,774	6,75,420
5	केस्को	कानपुर शहर	6,32,408	33,278
		यूपी- कुल	2,85,26,731	32,78,563

आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए निधि विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत जीबीएस	जारी की गई धनराशि		
			वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	815	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	54	-	-	-
4	असम	1,052	56	191	111
5	बिहार	412	169	17	-
6	छत्तीसगढ़	804	-	-	-
7	दिल्ली	2	-	-	-
8	गोवा	95	-	-	-
9	गुजरात	1,885	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	466	-	-	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	272	-	-	-
12	झारखंड	191	-	-	-
13	केरल	1,413	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	1,504	-	-	-
15	महाराष्ट्र	2,840	-	-	-
16	मणिपुर	38	-	-	-
17	मेघालय	86	-	-	-
18	मिजोरम	61	-	-	-
19	नागालैंड	60	-	-	-
20	पुदुचेरी	56	-	-	-
21	पंजाब	960	-	-	-
22	राजस्थान	1,686	-	-	-
23	सिक्किम	30	-	-	4
24	तमिलनाडु	3,398	-	-	-
25	त्रिपुरा	80	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	3,501	-	-	-
27	उत्तराखंड	310	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	2,089	-	-	31
	कुल	24,173	225	208	145

आरडीएसएस के तहत उत्तर प्रदेश में जिलेवार घरेलू विद्युतीकरण कार्य

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत घर	अब तक विद्युतीकृत घर
1	आगरा	1,173	0
2	अलीगढ़	1,795	0
3	औरैया	3,428	0
4	बाँदा	16,697	0
5	चित्रकूट	3,977	0
6	एटा	4,618	0
7	इटावा	625	0
8	फर्रुखाबाद	1,240	0
9	फिरोजाबाद	1,445	0
10	हमीरपुर	1,452	0
11	हाथरस	461	0
12	जालौन	955	0
13	झाँसी	3,976	0
14	कन्नौज	2,639	0
15	कानपुर देहात	3,749	0
16	कानपुर नगर	1,681	0
17	कासगंज	2,162	0
18	ललितपुर	2,341	0
19	महोबा	1,235	0
20	मैनपुरी	490	0
21	मथुरा	1,350	0
22	अंबेडकरनगर	2,853	0
23	अमेठी	1,945	0
24	अयोध्या	3,705	0
25	बहराइच	5,382	0
26	बलरामपुर	9,384	0
27	बाराबंकी	4,697	0
28	बरेली	2,052	0
29	शाहजहांपुर	2,325	0
30	गोंडा	44,217	0
31	हरदोई	3,928	0
32	खेरी	228	0
33	लखीमपुर	1,174	0
34	लखनऊ	943	0
35	पीलीभीत	1,200	0
36	रायबरेली	842	0
37	शाहजहांपुर	2,924	0

38	श्रावस्ती	4,735	0
39	सीतापुर	4,301	0
40	सुल्तानपुर	2,961	0
41	उन्नाव	2,820	0
42	आजमगढ़	2,304	33
43	बलिया	1,942	04
44	बस्ती	145	0
45	भदोही	514	0
46	चंदौली	934	0
47	देवरिया	3,829	0
48	फ़तेहपुर	3,920	0
49	गाजीपुर	143	0
50	गोरखपुर	1,995	0
51	जौनपुर	9,897	0
52	कौशांबी	3,750	0
53	कुशीनगर	119	0
54	कुशीनगर	16,189	0
55	महाराजगंज	76	0
56	महाराजगंज	3,291	0
57	मऊ	177	0
58	मिर्जापुर	6,669	0
59	प्रतापगढ़	15,540	0
60	प्रयागराज	21,071	25
61	संतकबीरनगर	13	0
62	संतकबीरनगर	65	0
63	सिद्धार्थनगर	327	03
64	सोनभद्र	5,135	0
65	वाराणसी	158	03
66	बिजनौर	392	195
	कुल	2,58,700	263

उपर्युक्त कुल में से:

- i. 316 पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों से संबंधित हैं।
- ii. 6,897 आदिवासी परिवार डीए-जेजीयूए (धरतीआबा जनजाति ग्राम उत्कर्षअभियान) के तहत चिह्नित किए गए हैं।
- iii. शेष परिवारों के लिए सामाजिक श्रेणी को शामिल नहीं किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1908
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

जमुई में विद्युत वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण

1908. श्री अरुण भारती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जमुई के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फीडर पृथक्करण की मौजूदा स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु चकाई, सोनो और खैरा जैसे क्षेत्रों में नए विद्युत उप-स्टेशन स्थापित करने अथवा मौजूदा उप-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत संस्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों की प्रगति **अनुबंध-1** पर दी गई है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत, भारत सरकार ने मुंगेर, शेखपुरा और जमुई जैसे जिलों सहित उन ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण का सक्रिय रूप से कार्य किया है जहाँ कृषि कार्य भार 30% से अधिक है। फीडर पृथक्करण कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	जिले	संस्वीकृत	पृथक्कृत
1	मुंगेर	25	25
2	शेखपुरा	29	25
3	जमुई	27	21
कुल		81	71

संस्वीकृत कार्यों के मार्च 2026 तक पूरा होने की अपेक्षा है।

(ग) : आरडीएसएस के अंतर्गत, कम वोल्टेज की समस्या को कम करने के लिए जमुई जिले के सोनो ब्लॉक के बटिया में एक नया 33/11 केवी 2x10 एमवीए विद्युत उपकेंद्र अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जमुई लोकसभा क्षेत्र के तीन जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत निम्नलिखित नए 33/11 केवी 2x10 एमवीए उपकेंद्र भी संस्वीकृत किए गए हैं:

- (i) जमुई जिले में इंडपे सबस्टेशन
- (ii) मुंगेर जिले में गढ़ीरामपुर (ऋषिकुंड) सबस्टेशन
- (iii) शेखपुरा जिले में मटोखर सबस्टेशन
- (iv) शेखपुरा जिले में गंगटी सबस्टेशन

(घ) : भारत सरकार ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में वितरण अवसंरचना में सुधार और एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- i. विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी का समय पर समाधान और भुगतान अनिवार्य करता है।
- ii. यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ और डू-अप आदेश समय पर जारी किए जाएं।
- iii. मशीन आधारित आंकड़ों के आधार पर उचित ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा अनिवार्य करना।
- iv. विद्युत क्षेत्र सुधारों से जुड़ी राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देना।
- v. डिस्कॉम के कार्य प्रदर्शन में सुधार और जवाबदेही के लिए तंत्र को सक्षम बनाने हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश।
- vi. आरडीएसएस भी ऐसी ही एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य एटीएंडसी हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 2.82 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। इनमें 1.51 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्य शामिल हैं, जिसमें अनावृत कंडक्टरों को ढके हुए कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंचड (एलटी एबी) केबल बिछाना और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)/सब-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्धन आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि के विभिन्न वित्तीय मापदंडों को वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन से जोड़ा गया है इनमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां और एसीएस-एआरआर अंतर प्रमुख हैं। इन कार्यों के निष्पादन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक भी है, जो एटीएंडसी हानियों में सुधार करने में सहायता करेगा।

केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गयी हैं।

दिनांक 24.07.2025 तक जमुई निर्वाचन क्षेत्र (जिले: मुंगेर, शेखपुरा और जमुई) में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत वितरण अवसंरचना के कार्यों का विवरण								
क्रम सं.	विवरण	यूओएम	मुंगेर		शेखपुरा		जमुई	
			संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि
स्मार्ट मीटरिंग कार्य								
1	उपभोक्ता मीटर	संख्या	55287	31280	21205	13329	24869	18382
2	फीडर मीटर	संख्या	109	106	57	71	96	103
3	डीटी मीटर	संख्या	3848	2779	1996	949	4166	3242
वितरण अवसंरचना कार्य								
4	नया विद्युत सबस्टेशन (2 x 10 एमवीए)	संख्या	1	0	2	0	2	0
5	33 केवी एचटी लाइन	सीकेएम	15.5	0	14	0	45	0
6	11 केवी एचटी लाइन	सीकेएम	629.77	450.09	668.91	463.11	789.28	626.1
7	एलटी लाइन	सीकेएम	1246.91	1164.39	1041.27	965.32	1436.21	1426.36
8	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	811	946	924	840	1265	1184
9	फीडर पृथक्करण	संख्या	25	25	29	25	27	21
10	अतिरिक्त घर	संख्या	206	0	0	0	1182	0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1912
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन की प्रति इकाई लागत

1912. श्री इमरान मसूद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से अब तक देश भर में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष-वार कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) संस्थापित क्षमता मार्च 2014 के 2,48,554 मेगावाट से बढ़कर जून 2025 में 4,84,819 मेगावाट हो गई है, जिसमें इस अवधि के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता 1,39,663 मेगावाट से बढ़कर 2,42,040 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) (बड़ी जलविद्युत सहित) की संस्थापित क्षमता 75,519 मेगावाट से बढ़कर 2,33,999 मेगावाट हो गई है।

- (ii) 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता के योग से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।
- (iii) सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क में छूट।
- (iv) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्ट्री।
- (v) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।
- (vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की संस्थापना।
- (vii) एटीएंडसी हानियों को वर्ष 2013-14 के 22.62% से घटाकर वर्ष 2023-24 में 16.28% करना। विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनको) के सभी वर्तमान भुगतान अद्यतन हैं और विद्युत उत्पादन कंपनियों का बकाया 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर 18,857 करोड़ रुपये हो गया है।
- (viii) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की, जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (> 25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना, जल विद्युत शुल्क कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता। तदुपरांत सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए (क) पूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, (ख) रेलवे साइडिंग, (ग) संचार अवसंरचना, और (घ) रोपवे हेतु बजटीय सहायता का दायरा दिनांक 08.10.2024 को विस्तारित किया गया है।
- (ix) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति की शुरुआत। इससे ताप विद्युत संयंत्रों को दक्ष घरेलू कोयला आवंटन संभव हुआ और विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनःप्रवर्तन भी सुनिश्चित हुआ।
- (x) उत्पादन क्षमता से पहले अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

(ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कोयले की कीमत और माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करती है, और मिश्रण के मामले में मिश्रित आयातित कोयले की कीमत पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग-आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती है। इसके अलावा, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का उपभोग करती है।

घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों को घरेलू कोयले की निरंतर आपूर्ति के साथ, आयातित कोयले के मिश्रण की परामर्शिका दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 से वापस ले ली गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच औसत विद्युत खरीद लागत में 5 पैसे की कमी आई है।

(घ): भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) निष्पक्ष, तटस्थ, दक्ष और स्थिर विद्युत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु पावर एक्सचेंजों की स्थापना।
- (ii) राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में अनुकूलन लाना।
- (iii) परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिंकेज स्रोतों का युक्तिकरण।
- (iv) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत खरीद हेतु टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी करना।
- (v) आरडीएसएस के अंतर्गत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी से यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे प्रणाली का बेहतर रखरखाव कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार विद्युत खरीद सकेंगे; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- (vi) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का प्रचालन।

देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार-
ब्यौरा:

वर्ष (31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	2,75,895
2015-16	3,06,330
2016-17	3,28,146
2017-18	3,45,631
2018-19	3,57,871
2019-20	3,71,334
2020-21	3,83,521
2021-22	3,99,497
2022-23	4,16,059
2023-24	4,41,970
2024-25	4,75,212
2025-26 (जून, 2025 तक)	4,84,819

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1914

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का विस्तार

1914. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रिड स्थिरता को समर्थन देने और परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुगम बनाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की स्थापना और विस्तार हेतु सरकार का रोडमैप क्या है;

(ख) भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊर्जा भंडारण अवसंरचना की, विशेषकर तमिलनाडु जैसे उच्च नवीकरणीय क्षमता वाले राज्यों में, प्रत्याशित भूमिका क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेषकर दक्षिणी ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद में देरी और जोखिमों को दूर करने के लिए ग्रिड अवसंरचना के आधुनिकीकरण और बितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) को सुव्यवस्थित करने के प्रयास कर रही है और यदि हाँ, तो किन प्रमुख पहलों का कार्य प्रगति पर है; और

(घ) सरकार द्वारा निवर्तमान विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) सुधार सह एकीकरण सहित तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण और उपशहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सौर, लघु पवन और हाइब्रिड प्रणालियों जैसे विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 41.6 गीगावाट / 208 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता का अनुमान लगाया है। बीईएसएस के विकास को सहायता देने के लिए, सरकार ने कई प्रमुख नीतिगत पहल की हैं:

- i) वर्ष 2023 में अनुमोदित एक व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) स्कीम, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक ₹ 3,760 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ बीईएसएस की 4,000 मेगावाट घंटा क्षमता को सहायता प्रदान करना था। बैटरी की घटती लागत के साथ,

अब लक्ष्य क्षमता को उसी बजट के भीतर रहते हुए बढ़ाकर 13,220 मेगावाट घंटा कर दिया गया है।

- ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा बीईएसएस की 30 गीगावाट घंटा क्षमता विकसित करने के लिए एक दूसरी वीजीएफ स्कीम को अनुमोदित किया है, जिसके लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से ₹ 5,400 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।
- iii) दिनांक 30 जून, 2028 तक चालू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

(ख) : वर्ष 2030 तक बीईएसएस और पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (ईएसएस), भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। ईएसएस उच्च पवन और सौर उत्पादन की अवधि के दौरान उत्पन्न अधिशेष विद्युत के भंडारण को सक्षम बनाता है, जिसे फिर उच्चतम मांग के दौरान डिस्पैच किया जा सकता है। ईएसएस को विद्युत प्रणाली के उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। इससे ग्रिड का अनुकूलन बेहतर होता है, पारेषण अवसंरचना का उपयोग बढ़ता है और नवीकरणीय ऊर्जा में कटौती कम होती है। इसके अलावा, ईएसएस आवृत्ति विनियमन और वोल्टेज नियंत्रण जैसी सहायक सेवाएँ प्रदान करने में भार पारेषण केंद्रों (एलडीसी) को सहायता करता है, जिससे समग्र ग्रिड विश्वसनीयता मजबूत होती है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु एक कार्यबल का गठन किया था, जिसने एक स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार ग्रिड बनाने हेतु एक व्यापक रोडमैप की सिफारिश की है। प्रमुख उपायों में मौजूदा पारेषण लाइनों का पुनः विद्युतीकृत करना, लचीली एसी पारेषण प्रणालियों (एफएसीटीएस) की स्थापना, और वास्तविक समय की स्थितियों के आधार पर विद्युत प्रवाह को अनुकूलित करने हेतु डायनेमिक लाइन लोडिंग (डीएलएल) को अपनाना शामिल है। कार्यबल ने पारेषण प्रणाली के उपयोग और अनुकूलन में सुधार हेतु ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थापना, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणालियों के उन्नयन, और पुराने सबस्टेशनों को गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) या हाइब्रिड सबस्टेशनों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव रखा है। कई सिफारिशों का कार्यान्वयन पहले से ही प्रगति पर है।

मंत्रालय ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत खरीद के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए हैं। सफल बोलीदाताओं को आरईआईए द्वारा जारी किए गए अवार्ड पत्र (एलओए) केवल एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे। यदि वितरण लाइसेंसधारी इस अवधि के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी (आरईआईए) के साथ पीपीए नहीं करते हैं, तो संबंधित एलओए रद्द माने जाएँगे। विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आरईआईए को बोलियाँ आमंत्रित करने से पहले वितरण लाइसेंसधारियों से माँग एकत्रित करने की सलाह दी गई है।

(घ) : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, डिस्कॉम रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री-कुसुम स्कीम के अंतर्गत, छोटे नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संयंत्रों का फीडर-स्तरीय एकीकरण लागू किया जा रहा है।

छतों पर सौर लगाए जाने को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 को फरवरी 2024 में संशोधित किया गया है ताकि प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और उपभोक्ता-उत्पादक के लिए संस्थापना में आसानी हो सके। प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं:

- 10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन से छूट।
- तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और अध्ययन के परिणाम आवेदक को सूचित किए जाएंगे, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।
- 5 किलोवाट तक की रूफटॉप प्रणालियों के लिए वितरण प्रणाली सुदृढीकरण की लागत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।
- डिस्कॉम द्वारा रूफटॉप सौर पीवी प्रणालियों को चालू करने की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दी गई है।

इन उपायों से रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी आने तथा तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उपभोक्ता भागीदारी बढ़ने की आशा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1925
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

जनजाति-बहुल गाँवों का विद्युतीकरण

1925. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने जनजाति-बहुल गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सौर-आधारित विद्युतीकरण प्रणालियों की कार्यकरण और विश्वसनीयता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी। सौभाग्य के तहत संस्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार पूरी हो चुकी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 पर संलग्न है)।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इसमें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत छूटे हुए घरों और पीएम-जनमन के अंतर्गत सभी चिन्हित घरों का विद्युतीकरण शामिल है। आरडीएसएस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिन्हित 1,27,061 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों के विद्युतीकरण के लिए 516 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई

है। इसके अलावा, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण संबंधित राज्य स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है। दिनांक 14.07.2025 तक, 1,23,446 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है)

इसके अतिरिक्त, नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत, 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49.8 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न है)।

(ख) : जिन क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी/आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां घरों को ऑफ-ग्रिड समाधानों, विशेष रूप से सौर-आधारित प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है, जैसा कि राज्यों द्वारा प्रस्तुत विवरण में बताया गया है।

नई सौर ऊर्जा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आदिवासी/पीवीटीजी परिवारों को प्रदान की जा रही ऑफ-ग्रिड प्रणाली में 5 वर्षों की व्यापक रखरखाव सेवाएँ शामिल हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दो वर्ष पूरे होने पर तृतीय-पक्ष निरीक्षण का भी प्रावधान है।

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित विद्युतीकृत घरों की संख्या।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

* सौभाग्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

पीएम-जनमन के अंतर्गत चिन्हित पीवीटीजी परिवारों का विद्युतीकरण (दिनांक 14/07/2025 तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत कुल परिवार	घरों का विद्युतीकरण
क					
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	7,144
3	झारखंड	74.13	44.47	12,442	5,341
4	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	313
6	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	24,036
7	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.94	8,603	6,235
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
उप-योग (क)		516	328	1,27,061	1,11,219
ख					
14	गुजरात				6,626
15	ओडिशा				2,229
16	पश्चिम बंगाल				3,372
उप-योग (ख)					12,227
कुल योग (क+ख)		516	328	1,27,061	1,23,446

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को मंजूरी दी गई

	राज्य	संस्वीकृत परिवारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,675
2.	छत्तीसगढ़	1,578
3.	झारखंड	2,342
4.	मध्य प्रदेश	2,060
5.	कर्नाटक	179
6.	केरल	98
7.	तेलंगाना	326
8.	त्रिपुरा	1,703
	कुल	9,961

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1935

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

दादरा और नागर हवेली में बिजली की कमी

1935. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में बिजली की कमी की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में उक्त स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) देश में, विशेषकर दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में, बिजली की कमी को कम करने या समाप्त करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.819 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 260.784 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष की स्थिति में परिवर्तित हो गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) की अवधि के लिए ऊर्जा की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

ये ब्यौरा दर्शाते हैं कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है और दोनों के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2019-20 में 0.5% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 0.1% और चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) में लगभग 0.0% हो गया है।

इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक विद्युत की कोई कमी दर्ज नहीं की गई है।

(ग) : विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भारत सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 526.4 मेगावाट फर्म पावर तथा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से 1,208.7 मेगावाट विद्युत आवंटित की है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने और विद्युत की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

1. उत्पादन योजना:

- (i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम माँग से आगे बनी रहे, सभी राज्यों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय चल योजनाएँ हैं और जिनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को अपनी संसाधन पर्याप्तता स्कीमों के अनुसार, सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजन की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:
 - (क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम **97,000 मेगावाट** कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस संबंध में कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से जून 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापीय क्षमताएँ पहले ही चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं सहित) तापीय क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापीय क्षमता के अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।
 - (ख) 13,463.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 9802 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
 - (ग) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 74,150 मेगावाट सौर ऊर्जा, 30,080 मेगावाट पवन ऊर्जा और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं, निर्माणाधीन है, जबकि 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, जिसमें 46,010 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल हैं, नियोजन के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ड) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 मेगावाट/49500 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 5780 मेगावाट/34680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) संस्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इनमें से 3500 मेगावाट/21000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) बोली प्रक्रिया के अधीन हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना:** अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि की समय-सीमा के अनुरूप इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. वितरण प्रणाली नियोजन:

(i) भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आईपीडीएस) शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(iii) भारत सरकार, सौभाग्य योजना के दौरान छोटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए, आरडीएसएस के अंतर्गत राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार

आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण हेतु संस्वीकृत किया जा रहा है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,486 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

- (iv) केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

4. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा:

- (i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोलियाँ जारी करने हेतु बोली प्रक्रिया जारी की है।
- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारिषद प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और उसके बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की अवधि वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- (v) ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारिषद उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

- (viii) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण किया गया है।
- (ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु रणनीति" जारी की गई है।
- (x) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी हेतु आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडबल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।

वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2020-2021 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र /क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,732	1,732	0	0	1,523	1,523	0	0
दिल्ली	33,086	33,077	9	0	29,560	29,555	4	0
हरियाणा	54,505	54,492	13	0	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	10,424	10,353	71	0.7	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	20,025	16,259	3,767	18.8	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	56,776	56,770	6	0	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	81,281	81,222	58	0.1	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	1,22,549	1,21,004	1,545	1.3	1,24,367	1,23,383	984	0.8
उत्तराखंड	14,472	14,376	96	0.7	13,827	13,818	8	0.1
उत्तरी क्षेत्र	3,94,851	3,89,285	5,566	1.4	3,96,151	3,92,323	3,829	1
छत्तीसगढ़	30,111	30,107	4	0	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	1,13,940	1,13,939	1	0	1,11,622	1,11,622	0	0
मध्य प्रदेश	76,172	76,172	0	0	83,437	83,437	0	0
महाराष्ट्र	1,55,167	1,55,166	0	0	1,50,679	1,50,663	16	0
दमन और दीव	2,574	2,574	0	0	2,223	2,223	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	6,528	6,528	0	0	5,497	5,497	0	0
गोवा	4,350	4,350	0	0	4,083	4,083	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	3,88,841	3,88,836	5	0	3,88,013	3,87,975	38	0
आंध्र प्रदेश	65,452	65,414	38	0.1	62,080	62,076	4	0
तेलंगाना	68,306	68,303	3	0	66,998	66,994	4	0
कर्नाटक	72,799	72,796	3	0	68,851	68,831	19	0
केरल	26,315	26,265	50	0.2	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	1,08,816	1,08,812	4	0	1,01,194	1,01,189	5	0
पुदुचेरी	2,847	2,846	1	0	2,644	2,644	0	0
लक्षद्वीप (#)	46	46	0	0	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,44,535	3,44,436	99	0	3,26,885	3,26,836	48	0
बिहार	31,627	31,533	94	0.3	34,171	34,018	153	0.4
झीवीसी	22,429	22,427	2	0	21,368	21,368	0	0
झारखंड	8,941	8,872	69	0.8	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	29,692	29,692	0	0	29,848	29,848	0	0
पश्चिम बंगाल	52,948	52,824	124	0.2	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	554	554	0	0	546	546	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	1,46,191	1,45,902	289	0.2	1,47,530	1,46,999	531	0.4
अरुणाचल प्रदेश	753	749	4	0.5	719	714	5	0.7
असम	9,804	9,288	516	5.3	10,192	9,815	377	3.7

मणिपुर	924	917	6	0.7	974	969	5	0.5
मेघालय	2,112	2,064	48	2.3	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	647	643	4	0.7	728	723	4	0.6
नागालैंड	814	809	5	0.7	826	822	4	0.5
त्रिपुरा (*)	1,538	1,515	23	1.5	1,484	1,481	3	0.2
पूर्वोत्तर	16,591	15,984	607	3.7	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारतीय	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी /विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,606	1,606	0	0
दिल्ली	31,128	31,122	6	0
हरियाणा	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	15,521	15,426	94	0.6
उत्तरी क्षेत्र	4,17,934	4,13,915	4,019	1
छत्तीसगढ़	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,72,823	1,72,809	14	0
दमन और दीव	2,594	2,594	0	0
दादरा और नगर हवेली	6,839	6,839	0	0
गोवा	4,448	4,448	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,29,065	4,28,683	383	0.1
आंध्र प्रदेश	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	70,539	70,523	16	0
कर्नाटक	72,437	72,417	20	0
केरल	26,579	26,570	9	0
तमिलनाडु	1,09,816	1,09,798	18	0
पुडुचेरी	2,894	2,893	1	0
लक्षद्वीप (#)	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,50,678	3,50,421	258	0.1
बिहार	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	23,741	23,736	4	0
झारखंड	11,148	10,590	558	5
ओडिशा	38,339	38,332	7	0
पश्चिम बंगाल	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	610	609	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	335	327	8	2.3
पूर्वी क्षेत्र	1,64,054	1,62,973	1,081	0.7
अरुणाचल प्रदेश	875	874	1	0.1
असम	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	656	644	12	1.8

नागालैंड	852	851	1	0.1
त्रिपुरा (*)	1,578	1,578	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,079	18,033	47	0.3
अखिल भारतीय	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	4,63,088	4,58,640	4,449	1	4,76,852	4,74,946	1,906	0.4
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	4,77,393	4,76,808	586	0.1	5,17,714	5,17,301	413	0.1
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप (#)	64	64	0	0	64	64	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	3,71,467	3,70,900	567	0.2	4,19,531	4,19,293	238	0.1
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.18562
पूर्वी क्षेत्र	1,82,791	1,80,888	1,903	1	1,92,013	1,90,747	1,266	0.7
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा (*)	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	78	0.4	20,022	19,733	289	1.4
अखिल भारतीय	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) की अवधि के लिए ऊर्जा के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित देश की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	ऊर्जा आपूर्ति (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	ऊर्जा आपूर्ति (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
			(एमयू)	(%)			(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	555	555	0	0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	11,303	11,299	4	0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	18,816	18,757	59	0.3
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	3,387	3,375	11	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	4,853	4,847	6	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	20,885	20,860	25	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	28,036	28,036	0	0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	46,028	46,022	6	0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	4,426	4,417	10	0.2
उत्तरी क्षेत्र	5,18,869	5,17,917	952	0.2	1,38,697	1,38,576	121	0.1
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	11,474	11,472	2	0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	41,752	41,752	0	0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	25,168	25,166	2	0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0	52,395	52,393	1	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,852	10,852	0	0	2,845	2,845	0	0
गोवा	5,411	5,411	0	0	1,486	1,486	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	5,28,924	5,28,701	223	0	1,38,472	1,38,466	6	0
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	20,471	20,471	0	0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	19,690	19,690	0	0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	22,945	22,945	0	0
केरल	31,624	31,616	8	0	8,015	8,015	0	0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	34,817	34,817	0	0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0	948	946	2	0.2
लक्षद्वीप (#)	68	68	0	0	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	4,25,373	4,25,349	24	0	1,06,899	1,06,897	2	0
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	12,716	12,713	4	0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	6,368	6,367	1	0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	3,931	3,930	1	0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	11,830	11,828	2	0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	20,645	20,626	18	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	128	128	0	0
अंडमान-निकोबार (#)	425	413	12	2.9	107	104	3	2.8
पूर्वी क्षेत्र	2,00,180	1,99,806	374	0.2	55,637	55,611	26	0
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	283	283	0	0
असम	12,843	12,837	6	0	3,506	3,506	0	0

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	274	272	2	0.9
मेघालय	2,046	2,046	0	0	494	494	0	0
मिजोरम	709	709	0	0	177	177	0	0
नागालैंड	938	938	0	0	243	243	0	0
त्रिपुरा (*)	1,939	1,939	0	0	512	512	0	0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	20,613	20,596	16	0.1	5,492	5,490	2	0
अखिल भारतीय	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	4,45,197	4,45,040	157	0

(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

(*) बांग्लादेश को निर्यात की गई ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है।

नोट: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1940
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता

1940. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या एनटीपीसी का अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा क्या विशिष्ट योजना बनाई गई है, और

(घ) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में, एनटीपीसी समूह (संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित) की संस्थापित क्षमता लगभग 82,895 मेगावाट है।

(ख) से (घ) : एनटीपीसी लिमिटेड ने एक 15-वर्षीय कॉर्पोरेट योजना तैयार की है जिसमें इसके विद्युत उत्पादन पोर्टफोलियो की परिकल्पना की गई है। वर्तमान कॉर्पोरेट योजना के अनुसार, एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 1,30,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विविध ईंधन मिश्रण का लाभ उठाते हुए, जीवाश्म ईंधन, जलविद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय स्रोतों को एकीकृत करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1951
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटरों की स्थापना संबंधी लक्ष्य

1951. श्री विष्णु दयाल रामः
श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्मार्ट मीटरों के प्रयोजनार्थ इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल परिव्यय और अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता कितनी है;

(ख) स्मार्ट मीटरों की जून 2025 तक स्थापित और स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ग) 2025 तक स्थापित किए जाने वाले स्मार्ट मीटरों की लक्षित संख्या कितनी है; और

(घ) क्या समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत भारत सरकार से 24,173 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ 1,30,671 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) : अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.45 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों की संस्थापना स्कीम अवधि (मार्च 2028) के अंत तक पूरी की जानी है।

(घ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

- i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य पर लाना है। इस स्कीम के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। इनमें 1.51 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्य शामिल हैं जिनमें कवर किए गए कंडक्टरों के साथ बेयर कंडक्टरों को बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी एबी) केबल बिछाना और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) / सब-स्टेशनों का उन्नयन / वृद्धि आदि शामिल हैं। स्कीम के तहत धनराशि जारी किया जाना विभिन्न वित्तीय मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटीयों के निष्पादन से जोड़ा गया है, जिनमें से एटीएंडसी हानियाँ और एसीएस-एआरआर अंतर प्रमुख हैं। इन कार्यों के क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग भी आरडीएसएस के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में एक है, जिससे एटीएंडसी हानियों में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति, जो उन पर विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर है।
- iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर होगा।
- iv. एफपीपीसीए और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के नियम जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतें वहनीय हैं।
- v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों और किए गए सुधार उपायों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी का एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1955
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

राजस्थान में डिस्कॉम का प्रदर्शन

1955. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्रों के स्थान और राज्य में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका क्या है;

(ख) राजस्थान में डिस्कॉम्स के प्रदर्शन में और विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों को पूरा करने तथा विद्युत हानियों को कम करने में किस प्रकार सुधार हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा झालावाड़-बारां, कोटा-बूंदी और राजस्थान के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कृषि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) राजस्थान में और विशेषकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा किसानों के लिए व्यवधान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राजस्थान में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा **अनुबंध-1** पर दिया गया है। ये विद्युत संयंत्र (राज्य, केंद्र और निजी स्वामित्व वाले) राज्य की आधार भार मांग (24x7) को पूरा करते हैं।

(ख) : राजस्थान डिस्कॉम्स ने अपने आरपीओ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत यूटिलिटी/ग्रिड स्केल सौर पार्कों से लेकर वितरित उत्पादन और सौर रूफटॉप एवं सौर पंप संस्थापना तक विविध प्रकार की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। इसमें पीएम-कुसुम के घटक-क का कार्यान्वयन शामिल है, जिसके अंतर्गत अब तक 602 मेगावाट क्षमता के 489 विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 457 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-कुसुम स्कीम के घटक-ग के अंतर्गत, राजस्थान डिस्कॉम्स ने 4,300 मेगावाट के 1696 पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 850 मेगावाट की परियोजनाओं से उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही, राज्य में पीएम-कुसुम-क स्कीम के अंतर्गत 4,700 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की संस्थापना के लिए निविदाएँ जारी की जा रही हैं।

पीएम-कुसुम स्कीम ने राजस्थान डिस्कॉम्स को कृषि माँग को पूरा करने और पारेषण/वितरण प्रणाली पर पूंजीगत व्यय और पारेषण हानियों को कम करने में सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप इस स्कीम के तहत कम टैरिफ प्राप्त हुए हैं, जिससे अंततः डिस्कॉम की औसत विद्युत क्रय लागत कम हुई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस के तहत राजस्थान राज्य के लिए वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए क्रमशः 18,693 करोड़ रुपये और 9,715 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। ये कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, वितरण यूटिलिटी के निष्पादन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कई अन्य पहल भी की गई हैं। विभिन्न सुधार उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, राजस्थान की यूटिलिटियों की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 26.23% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 22.08% हो गई है।

(ग) : भारत सरकार ने 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित भार फीडरों को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में अलग-अलग करने पर लगातार जोर दिया है। यह कुशल भार प्रबंधन में मदद करेगा, कृषि उपभोग के लिए आपूर्ति के विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग की सुविधा प्रदान करेगा और कृषि फीडरों के सौलरकरण को सक्षम करेगा जो आपूर्ति की लागत को कम करते हुए किसानों को दिन के समय आपूर्ति में मदद करेगा। आरडीएसएस के तहत, राजस्थान राज्य के लिए 10,201 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 12,835 कृषि फीडरों का पृथक्करण संस्वीकृत किया गया है, जिसमें से 248 फीडरों को पहले ही अलग किया जा चुका है और 12,587 फीडरों में पृथक्करण कार्य प्रगति पर है, जो स्कीम अवधि (मार्च, 2028) के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। संस्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं।

राज्य सरकार ने बताया है कि पिछले नौ महीनों के दौरान कोई विद्युत कटौती नहीं हुई है और तकनीकी खराबी के कारण कुछ रुकावटों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान डिस्कॉम ने घरेलू उपभोक्ताओं को औसतन 21 से 23 घंटे एकल-चरण विद्युत आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को 6 घंटे तीन-चरण ब्लॉक आपूर्ति प्रदान की है। किसानों को विद्युत आपूर्ति में होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय पर खराबी को ठीक करने, विद्युत लाइनों का नियमित रखरखाव, जले हुए ट्रांसफार्मरों को बिना किसी देरी के बदलने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

राजस्थान में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्रों का विवरण:

	विद्युत संयंत्र	जिला	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
राज्य स्वामित्व	सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र	सूरतगढ़, श्री गंगानगर	2,820
	कोटा ताप विद्युत संयंत्र	कोटा	1,240
	धौलपुर सीसीपीपी	धौलपुर	330
	छाबड़ा ताप विद्युत संयंत्र	बारां	2,320
	रामगढ़ गैस ताप विद्युत संयंत्र	रामगढ़	270
	कालीसिंध ताप विद्युत संयंत्र	झालावाड़	1,200
निजी पीपीपी	राजवेस्ट थर्मल पावर प्लांट	बाड़मेर	1,080
	अडानी पावर लिमिटेड	कवाई, बारां	1,200
केन्द्रीय क्षेत्र	राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र	कोटा	1,780
	एनएलसी थर्मल पावर प्लांट	बीकानेर	250

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1957

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

परिचालित विद्युत परियोजनाएँ

1957. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में परिचालित विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में उनका योगदान क्या है;

(ख) बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान राज्य में पिछले दस वर्षों के दौरान विद्युत कवरेज की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने गाँवों और घरों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अन्य परिवारों को प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अन्य परिवारों को निःशुल्क या रियायती विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बाड़मेर, जैसलमेर बऔर बालोतरा जिलों में वंचित परिवारों के लिए अंतिम सर्वेक्षण कब किया गया था और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(च) क्या इन जिलों में घरेलू कनेक्शनों के लिए कोई बजट आवंटित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित बस्तियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सुदूर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में, देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.81 गीगावाट है और 13.59 लाख एमवीए की रूपांतरण क्षमता वाली 4.95 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक) प्रचालनरत हैं।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है। हालांकि भारत सरकार विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने में राज्यों की मदद के उद्देश्य से उनके प्रयासों में सहायता कर रही है।

(ख) और (ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत, राजस्थान राज्य (बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) में कुल 427 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 1,49,854 परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य (बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) में सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 21,27,728 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया गया।

भारत सरकार चालू संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्य की सहायता कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत चिन्हित किए गए विशेष रूप से कमजोर सभी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिन्हित किए गए सभी जनजातीय परिवारों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। इस स्कीम के तहत, राजस्थान राज्य के लिए 4,39,177 घरों के विद्युतीकरण के लिए 1,764 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 95,986 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) : विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सब्सिडी सहायता प्रदान करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युतीकरण के लिए शेष घरों की पहचान के लिए अंतिम सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया था। इसके अलावा, लंबित आवेदनों की सूची एक परिवर्तनशील डेटा है जिसका रखरखाव संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा किया जाता है।

(च) : बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में विद्युतीकरण हेतु राज्य द्वारा चिन्हित लंबित घरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जिला	प्रस्तावित घर (संख्या)	संस्वीकृत घर	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1	बाड़मेर	3593	71,864	186.37
2	बालोतरा	1219	18,999	132.57
3	जैसलमेर	5076	34,455	141.03

(छ) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि कार्य जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

जैसा कि ऊपर भाग (क) में सूचित किया गया है, भारत सरकार ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वितरण अवसंरचना कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, चूँकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरस्थ, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। अब तक, आरडीएसएस के तहत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,486 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित घर भी शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1983
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों में स्टेलर का उपयोग

1983. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेलर नामक अत्याधुनिक, पूर्णतः स्वदेशी संसाधन पर्याप्तता मॉडल सभी राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को वितरित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य उपयोगिताओं और डिस्कॉम का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस उपकरण को अपनाया अथवा संचालित किया है;

(ग) वे शीर्ष तीन राज्य कौन से हैं जिनमें अपने पिछले संसाधन नियोजन मॉडल और स्टेलर द्वारा लगाए गए अनुमानों के बीच सबसे अधिक अंतर देखा गया है और उसके परिणामस्वरूप उनकी नीतियों अथवा अवसंरचना में क्या बदलाव आया है; और

(घ) उत्पादन, वितरण, भंडारण और सहायक सेवाओं के अनुकूलन में स्टेलर के उपयोग के कारण अनुमानित लागत बचत कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : सीईए द्वारा विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल (स्टेलर) मांग प्रतिक्रिया के साथ एक दीर्घकालिक क्षमता विस्तार मॉडल है। विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) की निगरानी समिति ने दिनांक 13.06.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, ₹5.35 करोड़ के पीएसडीएफ अनुदान से सीईए स्टेलर टूल के लिए 31 जीएमएस सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह टूल जल्द ही राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1987
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत क्षमता का विस्तार

1987. श्री सुधाकर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव चौसा ताप विद्युत संयंत्र में ताप विद्युत क्षमता को 800 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विस्तार की क्षमता सहित कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : बिहार के बक्सर जिले के चौसा गाँव में स्थित बक्सर ताप विद्युत परियोजना (बीटीपीपी) का विकास एसजेवीएन थर्मल पावर लिमिटेड (एसटीपीएल) द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसमें 660 मेगावाट की दो (02) इकाइयाँ हैं, जिसकी कुल क्षमता 1320 मेगावाट है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, किसी मौजूदा ताप विद्युत संयंत्र की क्षमता के विस्तार सहित किसी विद्युत संयंत्र की स्थापना देश में एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी तकनीकी-व्यावसायिक आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना एक उत्पादन स्टेशन स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1997
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

1997. श्री आदित्य यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 में कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र और उसके विनियमन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत जून, 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जिससे इसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित हो गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2019
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता

2019. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वार्षिक विद्युत उत्पादन कितना है और छत्तीसगढ़ सहित देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वार्षिक विद्युत उत्पादित हुई;

(ख) देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान वार्षिक क्षमता कितनी है और उनकी वार्षिक क्षमता सहित सभी चालू परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुल ऊर्जा घाटा और अधिकतम ऊर्जा घाटा कितना है; और

(ङ) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र किस प्रकार इस घाटे को कम करने में सहायक होगा?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मई-2025 तक) के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में उत्पादित वार्षिक विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : भारत में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान संस्थापित क्षमता 8,780 मेगावाट है (राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन-I (आरएपीएस-I) की 100 मेगावाट क्षमता को छोड़कर, जो विस्तारित शटडाउन के अधीन है)। सभी चालू परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की सूची उनकी निर्धारित क्षमता सहित **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग) : सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इस मिशन को सुगम बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को सक्षम बनाने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएँगे। सरकार ने लघु मॉड्यूल रिएक्टरों (एसएमआर) और नई उन्नत तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास को सक्षम बनाने के उपायों की भी घोषणा की है।

(घ) : वर्ष 2024-25 के दौरान ऊर्जा और उच्चतम मांग के संदर्भ में देश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-III** पर दी गई है। इससे पता चलता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान देश में ऊर्जा कमी और उच्चतम कमी लगभग शून्य थी।

(ङ) : न्यूक्लियर ऊर्जा विद्युत का एक स्वच्छ आधार स्रोत है जो 24x7 उपलब्ध है। न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र के संपूर्ण कार्यावधि के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जल और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के बराबर है। बजट-2025 में घोषित न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन की परिकल्पना की गई है। यह पहल, विकासशील भारत के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रणनीति हेतु भारत के ऊर्जा मिश्रण में न्यूक्लियर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाएगी।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मई-2025 तक) के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में उत्पादित वार्षिक विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(सभी आंकड़े एमयू में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उत्पादित विद्युत 2022-23	उत्पादित विद्युत 2023-24	उत्पादित विद्युत 2024-25	उत्पादित विद्युत 2025-26 (मई, 2025 तक)
अंडमान और निकोबार	252.45	375.29	413.18	71.38
आंध्र प्रदेश	81,701.42	90,081.32	92,072.29	16,442.46
अरुणाचल प्रदेश	4,845.79	4,280.73	4,207.04	577.73
असम	9,153.69	9,429.34	9,708.30	1,420.07
भूटान	6,742.40	4,716.10	5,484.18	731.51
बिहार	55,489.06	58,703.88	61,202.85	10,076.56
चंडीगढ़	12.61	11.70	8.79	1.06
छत्तीसगढ़	1,44,839.62	1,65,187.83	1,70,076.73	28,823.08
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	30.62	28.86	28.63	5.42
दिल्ली	4,314.50	4,483.95	4,626.96	840.80
गोवा	19.96	67.95	65.24	10.87
गुजरात	95,017.30	1,35,398.90	1,57,731.34	30,152.00
हरियाणा	33,559.00	29,848.93	32,681.55	5,035.18
हिमाचल प्रदेश	41,579.81	38,952.37	42,534.43	8,029.20
जम्मू और कश्मीर	17,170.62	16,282.93	15,595.82	3,780.96
झारखंड	30,800.35	35,984.77	39,105.22	5,874.21
कर्नाटक	85,189.36	91,468.95	1,00,182.18	16,907.17
केरल	9,935.38	7,359.96	9,458.66	1,735.62
लद्दाख	402.78	388.48	413.06	84.86
लक्षद्वीप	15.12	64.88	67.03	12.26
मध्य प्रदेश	1,52,020.26	1,64,779.83	1,66,290.81	27,634.41
महाराष्ट्र	1,58,993.39	1,69,037.91	1,70,242.07	30,463.61
मणिपुर	486.77	307.14	715.05	30.82
मेघालय	1,052.41	875.13	1,022.23	189.06
मिजोरम	266.40	217.74	317.79	18.89

नागालैंड	289.32	246.61	313.64	11.10
ओडिशा	71,529.15	73,443.73	76,221.89	13,617.23
पुदुचेरी	245.31	236.34	217.19	10.29
पंजाब	40,075.39	41,261.67	40,848.23	6,595.28
राजस्थान	1,05,963.47	1,16,845.30	1,30,771.79	24,665.97
सिक्किम	11,709.14	8,622.20	2,025.02	314.25
तमिलनाडु	1,16,688.02	1,23,311.63	1,30,124.92	20,675.49
तेलंगाना	64,178.16	65,666.12	69,881.68	11,925.68
त्रिपुरा	7,086.06	6,360.32	5,105.62	871.18
उत्तर प्रदेश	1,63,447.06	1,65,051.58	1,75,196.84	31,096.57
उत्तराखंड	16,368.16	15,459.95	16,955.30	2,410.80
पश्चिम बंगाल	92,995.30	94,250.84	97,784.38	16,176.99
कुल योग	6,24,465.61	17,39,091.19	18,29,697.94	3,17,320.01

निर्धारित क्षमता के साथ सभी चालू न्यूक्लियर ऊर्जा रिेक्टरों की सूची:

क्रम सं.	रिेक्टर और स्थान	क्षमता (मेगावाट)
1	आरएपीएस-2, रावतभाटा, राजस्थान	200
2	टीएपीएस-1, तारापुर, महाराष्ट्र	160
3	टीएपीएस-2, तारापुर, महाराष्ट्र	160
4	एमएपीएस-1, कलपक्कम, तमिलनाडु	220
5	एमएपीएस-2, कलपक्कम, तमिलनाडु	220
6	एनएपीएस-1, नरोरा, उत्तर प्रदेश	220
7	एनएपीएस-2, नरोरा, उत्तर प्रदेश	220
8	केएपीएस-1, काकरापार, गुजरात	220
9	केएपीएस-2, काकरापार, गुजरात	220
10	आरएपीएस-3, रावतभाटा, राजस्थान	220
11	आरएपीएस-4, रावतभाटा, राजस्थान	220
12	आरएपीएस-5, रावतभाटा, राजस्थान	220
13	आरएपीएस-6, रावतभाटा, राजस्थान	220
14	कैगा-1, कैगा, कर्नाटक	220
15	कैगा-2, कैगा, कर्नाटक	220
16	कैगा-3, कैगा, कर्नाटक	220
17	कैगा-4, कैगा, कर्नाटक	220
18	टीएपीएस-3, तारापुर, महाराष्ट्र	540
19	टीएपीएस-4, तारापुर, महाराष्ट्र	540
20	केएपीएस-3, काकरापार, गुजरात	700
21	केएपीएस-3, काकरापार, गुजरात	700
22	केकेएनपीपी-1, कुडनकुलम, तमिलनाडु	1,000
23	केकेएनपीपी-2, कुडनकुलम, तमिलनाडु	1,000
24	आरएपीएस-7, रावतभाटा, राजस्थान,	700

आरएपीएस: राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र

टीएपीएस: तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

एमएपीएस: मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र

एनएपीएस: नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

केएपीएस: काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र

केकेएनपीपी: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में ऊर्जा की कुल कमी और ऊर्जा की उच्चतम कमी

वर्ष	ऊर्जा				उच्चतम			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	ऊर्जा की आपूर्ति (एमयू)	अनापूर्ति ऊर्जा		उच्चतम मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग की आपूर्ति (मेगावाट)	उच्चतम मांग की आपूर्ति नहीं हुई	
			(एमयू)	(%)			(मेगावाट)	(%)
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2021
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के संचालन के लिए दिशानिर्देश

2021. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री मोहिबुल्लाह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के संचालन के लिए कोई कानूनी ढांचा या दिशानिर्देश जारी/स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार ढांचे के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में लागू नियमों, लेखा प्रोटोकॉल और सत्यापन तंत्रों का एक एकीकृत सेट स्थापित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए आधार वर्ष, उत्सर्जन कारक और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के प्रकार जैसे महत्वपूर्ण घटकों को निर्दिष्ट किया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने अनुकूलता सुनिश्चित करने और सीमा पार क्रेडिट हस्तांतरण या व्यापार को सक्षम बनाने के लिए भारत के कार्बन बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों या वैश्विक कार्बन बाजारों के साथ संरेखित करने हेतु कोई योजना तैयार की है या विचार कर रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है, जिसमें दो तंत्र परिभाषित किए गए हैं - अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र।

अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, 'बाध्यकारी संस्थाओं' के रूप में नामित उत्सर्जन-प्रधान उद्योगों को निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों का अनुपालन करना आवश्यक है। ऑफसेट

तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्यकारी संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, निष्कासन या इससे बचने के उद्देश्य से अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करा सकती हैं। दोनों तंत्रों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) ढाँचा शामिल है।

(ड) और (च) : भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए आधार वर्ष, उत्सर्जन कारक और विभिन्न क्षेत्रों को पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है। आठ विभिन्न क्षेत्रों नामतः लुगदी एवं कागज़, एल्युमीनियम, सीमेंट एवं क्लोर-क्षार, लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र में बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने वाली मसौदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए आठ कार्यप्रणाली भी प्रकाशित की गई हैं।

(छ) और (ज) : सीसीटीएस के कार्यान्वयन हेतु प्रकाशित उपरोक्त प्रक्रियाएँ वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। तथापि, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के सीमा-पार अंतरण या व्यापार संबंधी निर्णय, उभरती आवश्यकताओं के अनुसार, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीएआईएपीए) द्वारा लिए जाएँगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2029
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित स्लैग का निपटान

2029. श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा 500 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र संचालित कर रही है, जिसमें 100 मेगावाट की दो इकाइयां और 150 मेगावाट की दो इकाइयां हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त कोयले से उत्सर्जित स्लैग के निपटान हेतु क्या व्यवस्था की गई है और इस स्लैग को डंप किए जाने वाली जगह/स्थान कौन से है;

(ग) वर्ष 2024-25 से अब तक उत्सर्जित स्लैग की कुल मात्रा कितनी है; और

(घ) स्लैग बांध के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल, स्थान, प्रभावित गाँवों के नाम, स्लैग बांध की वर्तमान स्थिति आदि सहित इस हेतु प्रयुक्त की गई/प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी नहीं। मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा अपशिष्ट ताप रिकवरी बॉयलर पर आधारित 75 मेगावाट सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र और 162.5 मेगावाट कोयला आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र (1×12.5 मेगावाट + 6×25 मेगावाट) का प्रचालन कर रहा है।

(ख) और (ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से स्लैग उत्पन्न नहीं होता है। स्लैग इंडक्शन फर्नेस और सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 से अब तक उद्योग से उत्पन्न स्लैग की मात्रा 3,90,402 टन है।

(घ) : मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा कोई स्लैग बांध का निर्माण नहीं किया गया है और स्लैग बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2044
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण

2044. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा में कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई और राज्य की विद्युत आपूर्ति में इसका कितना योगदान है;

(ख) विगत छह महीनों के दौरान राज्य में, विशेषकर बिजली की कमी वाले और कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में, अनिर्धारित विद्युत कटौती की संख्या और संचयी अवधि कितनी है;

(ग) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत ओडिशा में होने वाली समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी और सी) हानि में कितनी कमी आई है और भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत परेल् विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में सौर-आधारित दोहरो पंप प्रणालियों की स्थापना सहित विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा में 125.83 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। इस क्षमता वृद्धि से वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 220.61 मिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति हुई है, जिससे नवीकरणीय स्रोतों से कुल खपत बढ़कर 10,370.11 मिलियन यूनिट हो गई है।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले छह माह (जनवरी-जून 2025) के दौरान अनिर्धारित विद्युत कटौती की संचयी संख्या और अवधि पर डिस्कॉम-वार डेटा अनुबंध पर है।

(ग) : ओडिशा, उदय स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में एटीएंडसी हानि 16.55% थी।

(घ): राज्य के सभी राजस्व गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। सर्वेक्षण में चिन्हित शेष बचे घरों का विद्युतीकरण राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत किया जा रहा है।

विभिन्न उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार के ओडिशा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम (ओडीएसएसपी) चरण-IV और V स्कीमों के अंतर्गत नए 33/11 केवी प्राथमिक सबस्टेशन (पीएसएस) की संस्थापना, मौजूदा 33/11 केवी पीएसएस का सुदृढीकरण, नई 11 केवी लाइनें और ट्रांसफार्मर लगाना तथा मौजूदा 11 केवी लाइनों का सुदृढीकरण जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, डिस्कॉम अपनी स्वयं की कैपेक्स के अंतर्गत प्रणाली सुदृढीकरण कार्य कर रही हैं।

कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों सहित सभी सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप परियोजनाओं का नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है।

पिछले छह माह (जनवरी - जून 2025) के दौरान राज्य में रिपोर्ट की गई अनिर्धारित विद्युत कटौती की संचयी संख्या और अवधि पर डिस्कॉम-वार आंकड़े:

डिस्कॉम	संचयी अनिर्धारित आउटेज की संख्या	अनिर्धारित आउटेज की संचयी अवधि (घंटों में)
टीपीसीओडीएल	94	56
टीपीएसओडीएल	128	102
टीपीएनओडीएल	237	121.01
टीपीडब्ल्यूओडीएल	176	144

टिप्पणी: (कंधमाल में: संचयी अनिर्धारित आउटेज की संख्या 53 थी और अनिर्धारित आउटेज की संचयी अवधि 47 घंटे थी।)

टीपीसीओडीएल: टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।

टीपीएसओडीएल: टाटा पावर साउदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।

टीपीएनओडीएल: टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।

टीपीडब्ल्यूओडीएल: टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2050
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों में वायु गुणवत्ता

2050. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान पेड्डापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संचालित एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों में दर्ज वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा क्या है, जिसमें कणिकीय पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर शामिल हैं;

(ख) विध्याचल में प्रतिदिन 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को मापने वाली सफल प्रायोगिक परियोजना के बाद जिले में एनटीपीसी सुविधाओं में कार्बन कैपचर तकनीक की तैनाती की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने पेड्डापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले समुदायों पर स्वास्थ्य प्रभाव आकलन अध्ययन किए हैं और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं;

(घ) ताप विद्युत उत्पादन कार्यों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आने वाले प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा निधि का आवंटन कितना है; और

(ङ) केंद्र सरकार की प्रदूषण न्यूनीकरण नीति के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक पुरानी कोयला संचालित इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : एनटीपीसी लिमिटेड वर्तमान में तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के पेड्डापल्ली लोकसभा क्षेत्र में अपने दो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) का प्रचालन कर रही है, जिनके नाम हैं रामागुंडम (2,600 मेगावाट) और तेलंगाना (1,600 मेगावाट) ताप विद्युत संयंत्र, जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं।

टीपीपी के निकट विभिन्न स्थानों पर पिछले बारह महीनों के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से दर्ज और निगरानी किए गए कणिकीय पदार्थों तथा सल्फर डाइऑक्साइड सहित उत्सर्जन स्तरों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा अनुबंध पर हैं।

(ख) : एनटीपीसी लिमिटेड ने फ्लू गैस CO₂ कैप्चर और उपयोग के लिए निम्नलिखित लघु-स्तरीय पायलट/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की हैं:

- (i) एनटीपीसी विंध्याचल, मध्य प्रदेश में 10 टन प्रतिदिन फ्लू गैस CO₂-से-मेथनॉल परियोजना।
- (ii) एनटीपीसी लारा, छत्तीसगढ़ में 10 टन प्रतिदिन फ्लू गैस CO₂-से-जनरेशन-4 इथेनॉल परियोजना।

परियोजनाएँ अभी प्रदर्शन चरण में हैं। अभी तक, तेलंगाना के पेड्डापल्ली ज़िले में स्थित एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों में कार्बन कैप्चर तकनीक के इस्तेमाल के लिए कोई योजना नहीं है।

(ग) : पेड्डापल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों के दस किलोमीटर के कार्यक्षेत्र में रहने वाले समुदायों पर स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, एनटीपीसी रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र ने 2x800 मेगावाट तेलंगाना सुपर ताप विद्युत को शामिल करने के लिए वर्ष 2017-18 में स्वतंत्र रूप से "व्यावसायिक स्वास्थ्य और महामारी स्वास्थ्य विकार सर्वेक्षण" कराया था जिसमें अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य जोखिम, महामारी विज्ञान अध्ययन और पारिस्थितिक जोखिम भी शामिल थे। अध्ययन के अनुसार, टीपीपी के आसपास के क्षेत्रों में कोई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव रिपोर्ट नहीं किया गया।

(घ) : पेड्डापल्ली ज़िले में एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्रों को मुआवज़े के लिए ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, एनटीपीसी लिमिटेड के ये संयंत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 31.12.2021 की ऐश अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार अपनी फ्लाइंग ऐश का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कर रहे हैं।

(ङ) : नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, एनटीपीसी लिमिटेड ने पेड्डापल्ली जिले में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र और 10 मेगावाट का ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी ताप विद्युत यूटिलिटी को दिनांक 20.01.2023 और दिनांक 07.07.2023 को एक परामर्श जारी किया है कि वे वर्ष 2030 से पहले अपने कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों को बंद या किसी अन्य उद्देश्य से उपयोग न करे और भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा मांग परिदृश्य को देखते हुए, यदि आवश्यक हो तो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) गतिविधियों को पूरा करने के बाद ताप यूनिट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-7 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है और यूनिट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक, ऊर्जा मांग और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर किया जाता है।

एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्र, पेड़पल्ली- जिला के पास परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा

क्रम सं.	महीने/ मापदंड	स्थल-1: संतुलन जलाशय				स्थल-2: रामागुंडम पंप हाउस				स्थल-3: स्थायी टाउनशिप			
		पीएम-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा: 100	पीएम -2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:60	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80	पीएम -10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा: 100	पीएम -2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:60	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80	पीएम -10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा: 100	पीएम -2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:60	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), सीमा:80
1	जून 2024	38.26	21.60	15.60	24.80	59.15	42.24	12.52	20.79	54.26	37.47	9.51	16.80
2	जुलाई 2024	37.62	21.93	15.68	23.12	44.35	33.28	13.03	20.69	45.63	33.64	9.51	17.95
3	अगस्त 2024	37.46	19.19	17.55	24.26	39.22	19.14	13.45	21.81	39.24	19.86	9.81	17.91
4	सितंबर 2024	38.29	18.42	18.48	25.43	40.17	19.10	13.37	20.59	38.79	20.58	9.99	18.21
5	अक्टूबर 2024	39.94	20.14	20.25	25.02	41.25	20.93	13.66	21.24	40.78	21.32	10.26	19.48
6	नवंबर 2024	43.99	22.17	21.89	25.68	43.61	22.35	13.80	23.01	43.55	24.13	11.56	20.64
7	दिसंबर 2024	48.84	24.47	23.73	25.63	48.37	22.87	15.29	24.97	46.76	26.76	13.36	21.78
8	जनवरी 2025	52.60	26.66	24.13	25.96	51.28	25.66	17.08	26.03	50.75	28.33	16.49	22.75
9	फरवरी 2025	53.59	26.41	25.36	26.48	51.64	26.03	17.81	24.72	52.70	27.77	17.47	23.94
10	मार्च 2025	54.68	26.30	16.05	28.05	53.00	26.50	14.16	25.57	54.66	28.17	14.68	23.15
11	अप्रैल 2025	56.78	27.36	10.82	18.27	55.47	26.19	11.13	16.83	56.12	28.86	11.87	20.87
12	मई 2025	45.51	23.44	11.44	18.79	44.59	24.58	11.37	18.10	45.16	25.67	12.79	19.79

नोट: यह डेटा सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा की गई द्वि-साप्ताहिक 24-घंटे की निगरानी के मासिक औसत पर आधारित है।